The Board has been assigned the task of suggesting levels of development expenditure over the area of the Development Board during a plan period including the annual plans.

योजना आयोग की कार्य-प्रणाली में परिवर्तन

1821. **श्री राम जेठमलानी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आज देश में बदलती हुई परिस्थितियों को देखते हुए वर्तमान योजना आयोग की कार्य-प्रणाली में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या कतिपय परिवर्तनों के प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो वे प्रस्ताव क्या-क्या हैं और प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला देहरेश्वर सवनूर): (क) से (ग) राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 16 जनवरी, 1997 को अनुमोदित नौवीं योजना (1997-2002) संबंधी एप्रोच पेपर में योजना तैयार करने और प्राथमिकताओं की पहचान के लिए योजना आयोग द्वारा पालन की जाने वाली विस्तृत एप्रोच निर्धारित की है। नौवीं योजना अवधि के दौरान, योजना तैयार और योजना प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण में अनेक परिवर्तन अपेक्षित हैं, इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्र प्रयोजित स्कीमों का राज्यों को स्थानान्तरण, योजना तैयार करने में राज्यों की अधिक भागीदारी और पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों को अधिक अधिकार देना और कतिपय सामाजिक क्षेत्रकों में बुनियादी न्यूनतम सेवा के कार्यान्वयन में पालन की जा रही एप्रोच को अपनाना एवं कुछ क्षेत्रकों की गहराई से योजना तैयार करना शामिल है।

दृष्टिकोण पत्र में निहित निर्देशों द्वारा योजना आयोग के कार्यों का मार्गदर्शन होगा और नये परिवर्तनों के अनुसरण में ऐसे आवश्यक परिवर्तन किये जायेंगे।

Creation of Youth Cell in the Planning Commission

1822. SHRI VEDPRAKASH P. GOYAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether any Youth Cell has been created in the Planning Commission for various Development Schemes/Programmes for the Youth of the country; and

(b) whether any Member of the Planning Commission has also been associated with the cell; if so, the name of that Member?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRIMATI RATNAMALA DEHARESHWAR SAVANOOR): (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

Annual Plan outlay for Punjab

1823. SHRI IQBAL SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the annual plan outlay for 1997-98 sought by Punjab and the outlay sanctioned;

(b) the industrial and agricultural growth rates contemplated thereunder;

(c) the targets fixed thereunder; and

(d) what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRIMATI RATNAMALA DEHARESHWAR SAVANOOR): (a) to (d) The annual Plan 1997-98 outlay of Rs. 2100 crore for the Punjab state was agreed upon in the meeting held between the Deputy Chairman, Planning Commission and the Chief Minister of the State. A growth rate of 9.50% in the Industrial Sector and 2.16% in the Agriculture (including Livestock) Sector is contemplated by the State Government of Punjab for the Annual Plan 1997-98. The production of Foodgrains, Sugarcane and Cotton is targetted at 209.66 lakh tonnes, 90.00 lakh tonnes and 22.00 lakh bales respectively.